भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 983
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी

983. श्री टी रतिनावेल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय ऑटोमोबाइल पुनर्विनिर्माण बाजार और अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है, जिसके कारण नवोन्मेषकारी प्रौद्योगिकी की उपादेयता बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या भारतीय आटो निर्माता को नवीनतम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार भारत को वास्तविक रूप से वैश्विक ऑटो निर्माता बनाने के लिए ऑटो उद्योग को नवीनतम प्रौद्योगिकी और उपकरण प्राप्त करने के लिए मदद देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा कार विनिर्माता, 7वां सबसे बड़ा वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता और दुपहियों का सबसे बड़ा विनिर्माता है। भारतीय ऑटो उद्योग ने ऑटो कल्पुर्जा उद्योग के साथ-साथ वाहनों में वैश्विक ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियां अपनाई हैं और इसके परिणामस्वरूप, नवीनतम विनिर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है जो उच्च स्तरीय ऑटोमेशन की तुलना में अधिक जन उन्मुख है जो विश्व में अन्यत्र प्रचलित है।

(ख): जी हां, ऑटोमोटिव उद्योग में तेजी से बदलती उत्पाद प्रौद्योगिकियों और कम होते जीवाश्म ईंधन संसाधनों, इसकी उच्च आयात लागत, पर्यावरणीय दूर्दशा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के मद्देनजर, पारंपरिक आईसी इंजन आधारित वाहनों से इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, ईंधन सेलों जैसी नई ड्राइवट्रेन प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करना समय की मांग है। इस प्रकार उद्योग को ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों और बैटरी प्रबंधन प्रणालियों के लिए लिथियम ऑयन बैटरियों, इलेक्ट्रिक मोटरों जैसी प्रौद्योगिकियां विकसित करने की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ): जी हां, सरकार ने मिशन मोड में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, 2013 मिशन तैयार किया है। इसके अनुकरण में मांग सृजन को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराने, ईवी ईकोसिस्टम और अवसंरचना की स्थापना और

अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी के विकास हेतु वर्ष 2015 में फेम स्कीम आरंभ की गई। इस स्कीम (फेम-2) के दूसरे चरण में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों सहित मांग और आपूर्ति की दिशा में अनेक हस्तक्षेपों के साथ ईवी उद्योग को बढ़ावा देने की परिकल्पना है।

इसके अलावा, भारी उद्योग विभाग उत्पाद हेतु दिए गए अनुदानों के माध्यम से समय-समय पर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे, शैक्षणिक संस्थानों आदि को ऑटोमोबाइल एवं संबद्ध उद्योग विकास परिषद (डीसीएएआई) निधियों के माध्यम से अवसंरचना विकास के परीक्षण में सहायता करता है।

******